RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 318
दि. 22.03.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

माई भारत राष्ट्रव्यापी शहीद दिवस पदयात्रा 2026 का आयोजन करेगा 'मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी' थीम के तहत 763 जिलों में

केन्द्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे और हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम 23 मार्च 2026 को फरीदाबाद में युवाओं की अगुवाई वाली राष्ट्रव्यापी शहीद दिवस पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे

(जीएनएस)।

भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानियों – शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम राजगुरु और शहीद सुखदेव थापर – के अद्वितीय बलिदान को पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत (माई भारत) के माध्यम से शहीद दिवस के उपलक्ष्य में 23 मार्च, 2026 को एक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का आयोजन करेगा। यह पहल 'मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी' थीम के तहत संचालित की जाएगी।

हर वर्ष, शहीद दिवस इस बात की सशक्त स्मृति प्रदान करता है कि भारत की आजादी बलिदान और साहस के बल पर अर्जित की गई थी। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि आजादी महज विरासत में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर सामूहिक प्रयासों से इसे मजबूत और संरक्षित भी किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में, शहीद दिवस पदयात्रा युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके स्मरण को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करती है।

दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक के रूप में भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को देखते हुए, इस पहल का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, आदर्शवाद और आकांक्षाओं को जिम्मेदार नागरिकता की ओर निर्देशित करना है। 'मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी' की थीम अतीत के बलिदानों का सम्मान करने से लेकर भविष्य के कर्तव्यों को स्वीकार करने तक के बदलाव को दशार्ती है।

देश के सभी 763 जिलों में पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें से एक प्रमुख आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में होगा, जिसमें 10,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। एक एकीकृत राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में युवाओं के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी।

फरीदाबाद में होने वाली पदयात्रा राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का मुख्य आयोजन होगी और इसमें केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे और हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे, जिनकी उपस्थिति से युवाओं की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होगी।

फरीदाबाद में, यह पदयात्रा के.एल. मेहता दयानंद कॉलेज (प्रारंभिक बिंदु) से शुरू होगी और घंटा घर, मार्केट नंबर 5 (केसी रोड) सहित प्रमुख स्थलों से होते हुए लगभग 2.31 किलोमीटर की दूरी तय करके शहीद भगत सिंह चौक (एनएच-5) पर समाप्त होगी।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना से प्रेरित होकर, माई भारत युवाओं में नागरिक चेतना को बढ़ावा देने हेतु लगातार ऐसे आयोजन करता रहता है। अब तक 13 राष्ट्रीय स्तर की विकसित भारत पदयात्राएं, 108 राज्य स्तर की पदयात्राएं और 1,573 जिला स्तर की पदयात्राएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 21 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया है। इन प्रयासों ने सामूहिक रूप से युवा नागरिकों में स्वयंसेवा, देशभक्ति और नागरिक उत्तरदायित्व की सशक्त संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया है।

इस पदयात्रा से पहले, लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें माई भारत पोर्टल (ट्ठ१३.ॅड्ड५.ल्ल) पर गुमनाम नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित प्रश्नोत्तरी के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान और युवाओं की रचनात्मक

अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने वाली 'एक युवा ऐसा भी' थीम पर आधारित एक रील प्रतियोगिता शामिल है।

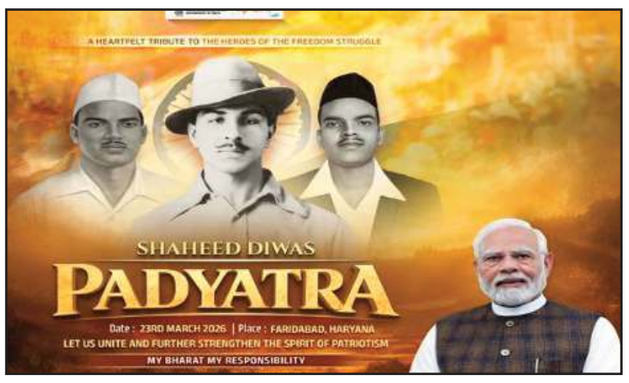

इसके अलावा, एक राष्ट्रव्यापी प्रयास के तहत, 22 मार्च, 2026 को माई भारत सिविक सेंस चैलेंज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी जिलों में श्रमदान गतिविधियां शामिल होंगी। इन गतिविधियों में स्वच्छता अभियान और सड़क सुरक्षा जागरूकता पहल शामिल हैं, जो सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करेंगी। एक विशेष 'मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी' शपथ पटल स्थापित की जाएगी, जिससे प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकेंगे।

शहीद दिवस पदयात्रा भारत की विकास गाथा में सक्रिय योगदान देने के लिए युवाओं को आगे आने का राष्ट्रव्यापी आ'ान है। यह युवा नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित करने, एकता के बंधन को मजबूत करने और देशभक्ति की भावना को बनाए रखने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करता है। देश भर के युवाओं से इसमें भाग लेने, जिम्मेदार नागरिकता की शपथ लेने और सकारात्मक परिवर्तन के उत्प्रेरक बनने का आग्रह किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, माई भारत पोर्टल पर जाएं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इस्लामिक गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मसूद पेजेश्कियन से बात की। उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन को ईद और नवरोज के शुभ अवसरों पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। चर्चा के दौरान, दोनों नेताओं ने उम्मीद व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि का दौर लेकर आएगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। प्रधानमंत्री ने नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के अत्यधिक महत्व को दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग खुले और सुरक्षित रहें। इसके अलावा, श्री मोदी ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में ईरान के निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने पर लिखा:

"राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से बात की और ईद तथा नवरोज की शुभकामनाएँ दीं। हमने उम्मीद जाहिर की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाएगा।

क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं।

नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया कि शिपिंग मार्ग खुले और सुरक्षित रहें।

मथुरा में फरसे वाले बाबा की मौत पर हंगामा, सीएम योगी बोले- अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे

लखनऊः (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोरक्षक फरसे वाले बाबा की मौत के बाद शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि गोतस्‍करों ने उन्हें कंटेनर से कुचल दिया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने सड़क उतर कर दिल्ली-आगरा हाईवे को जामकर जमकर बवाल काटा है। इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराधी किसी हाल में बख्शे न जाएं।

सीएम योगी ने फरसे वाले बाबा के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है। साथ ही

अधिकारियों को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

चीजों को नफरत में बदलना बीजेपी से सीखिए: अखिलेश

वहीं, इस घटना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें इस बारे में सोचना होगा कि इखढ कहां तनाव पैदा कर सकती है। उन्‍होंने कहा कि अब यहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं बची है। अगर किसी को यह सीखना है कि चीजों को नफरत में कैसे बदला जाता है, तो वे इखढ से सीख सकते हैं।

अगर मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर एक साधु के साथ ऐसा बर्ताव होता है, और काशी में जहां से प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, वहां एक छात्र सरेआम दूसरे छात्र की हत्या कर देता है तो पूरे प्रदेश में कोई भी, जो चाहे कर सकता है।

सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव

मथुरा में हालात नियंत्रण में: डीआईजी शैलेश पांडे

इस घटना को लेकर आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश पांडे ने बताया कि तड़के सुबह बरसाना थाना क्षेत्र के रहने वाले बाबा ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर मवेशियों की तस्करी के शक में एक ट्रक को रोक लिया था। उस समय घना कोहरा था और पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने रुके हुए ट्रक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में फरसे वाले बाबा घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत के बाद उनके कुछ समर्थकों और

श्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में आयोजित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 45 वीं बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में आयोजित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 45 वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान चिड़ियाघरों के प्रभावी प्रबंधन मूल्यांकन के दूसरे चरण के प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

' मेरा चिड़ियाघर ' की अवधारणा पर एक समिति का गठन किया जाए ताकि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को चिड़ियाघरों से जोड़ा जा सके।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की आगामी बैठकों में चिड़ियाघरों द्वारा प्रति बैठक 2 से 3 प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन पर हुई प्रगति को प्रस्तुत किया जाएगा।

मानव-तेंदुआ नकारात्मक अंतःक्रियाओं में शामिल तेंदुओं को उन चिड़ियाघरों में स्थानांतरित करने के संबंध में अद्यतन जानकारी दी जानी चाहिए , जिन चिड़ियाघरों ने

उनके दीर्घकालिक देखभाल के लिए दूर क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता की सूचना दी हो और जो उचित आवास, रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करती हों।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर के आधुनिकीकरण की अवधारणा को अन्य चिड़ियाघरों के लाभ के लिए साझा किया जा सकता है।

चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों के लिए बंदी पशुओं के पोषण पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

आगामी बैठकों में नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अगली बैठक में चिड़ियाघर निदेशक द्वारा एक प्रस्तुति को शामिल किया जाए।

बैठक के दौरान 'कैद में देखभाल: चिड़ियाघरों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने वाला संकलन' शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया। यह संकलन पशु कल्याण, संरक्षण प्रजनन, अनुसंधान और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए चिड़ियाघर प्रबंधन के प्रति भारत के विकसित होते दृष्टिकोण को उजागर करता है।

असम, केरल और पुडुचेरी में ईवीएम-वीवीपीएटी का पहला यादृच्छिकीकरण कार्य पूरा

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और छह राज्यों में उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। ईवीएम का आवंटन दो चरणों वाली यादृच्छिक प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित मतदान केंद्रों को किया जाता है। पहले चरण में, जिला स्तरीय गोदामों से विधानसभा क्षेत्रों को ईवीएम का यादृच्छिक आवंटन किया जाता है। दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र स्तर से मतदान केंद्र स्तर तक ईवीएम का यादृच्छिक आवंटन किया जाता है। ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, सभी मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीईओ को एफएलसी में मानकों को पूरा करने वाली ईवीएम-वीवीपीएटी मशीनों का पहला यादृच्छिकीकरण पूरा करना होगा।

नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत 'तारागिरी' को कमीशन करने के लिए तैयार

भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत 'तारागिरी' को कमीशन करने के लिए तैयार है

समुद्र का एक नया हरावल: तारागिरी भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति में शामिल होने के लिए तैयार है

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना, भारत की समुद्री संप्रभुता के एक निर्णायक समारोह में 3 अप्रैल 2026 को अपने नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत, तारागिरी (एफ41) को कमीशन करने की तैयारी कर रही है। विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले इस समारोह की अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह राष्ट्र के पूर्णतः आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का एक सशक्त प्रमाण होगा।

प्रोजेक्ट 17ए श्रेणी के चौथे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में तारागिरी केवल एक युद्धपोत नहीं है; यह 6,670 टन का 'मेक इन इंडिया' भावना और हमारे स्वदेशी शिपयार्डों की परिष्कृत इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रतीक है।

मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित यह युद्धपोत अपने पूर्ववर्ती डिजाइनों की तुलना में एक पीढ़ीगत विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसका

आकार अधिक सुव्यवस्थित है और इसमें कम रडार क्रॉस-सेक्शन है, जिससे यह घातक स्टील्थ तकनीक से कार्य करने में सक्षम है। 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना यह युद्धपोत घरेलू औद्योगिक तंत्र की परिपक्वता को दशार्ता है। इस कार्य में अब 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं। जो भारत सरकार की आत्मनिर्भरता पहल में योगदान करते हुए हजारों भारतीयों को रोजगार प्रदान करते हैं।

तरागिरी एक संयुक्त डीजल या गैस (सीओडीओजी) प्रणोदन संयंत्र द्वारा संचालित है, जिसे 'उच्च गति- उच्च सहनशक्ति' की बहुमुखी प्रतिभा और अनेक समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। युद्धपोत का हथियार भंडार विश्व स्तरीय है। इसमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली हैं। ये प्रणालियाँ अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निर्बाध रूप से एकीकृत हैं जिससे चालक दल पलक झपकते ही खतरों का जवाब दे सकता है। समुद्र में अग्रणी शिकारी होने के अलावा, तारागिरी आधुनिक कूटनीति और मानवीय संकटों की जटिलताओं के लिए भी उपयुक्त है। इसकी अनुकूल मिशन प्रोफाइल इसे उच्च-तीव्रता वाले युद्ध से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) तक हर चीज के लिए आदर्श बनाती है।

भारतीय नौसेना एक युद्ध-परिचित, एकजुट, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर बल के रूप में निरंतर विकसित हो रही है, जो भारतीयों द्वारा डिजाइन किए गए, भारतीयों द्वारा निर्मित और भारतीयों द्वारा संचालित जहाजों से संरक्षित विकसित और समृद्ध भारत के लिए समुद्रों की रक्षा कर रही है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने प्रकृति 2026 का उद्घाटन किया

भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल का शुभारंभ करते हुए भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ किया

कार्बन बाजार नवाचार और सतत विकास के चालक के रूप में स्थापित हैं

(जीएनएस)।

भारत सरकार का प्रमुख आयोजन 'प्रकृति 2026'—कार्बन बाजारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन—आज नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा, विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित यह सम्मेलन 'भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026' के अंतर्गत हो रहा है। यह उच्च स्तरीय मंच राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति-निमार्ताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और शोधकताओं को एक साथ लाकर कार्बन बाजारों की बदलती गतिशीलता, जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका तथा भारत के हरित विकास के अवसरों पर व्यापक विचार-विमर्श का अवसर प्रदान

करता है।इस वर्ष की विषयवस्तु 'वैश्विक साझेदारी और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से एनडीसी कार्यान्वयन हेतु कार्बन वित्त को सुगम बनाना' है, जो जलवायु कार्रवाई को गति देने के लिए वित्तीय संसाधनों के संकलन, सहयोग को सुदृढ़ करने व डिजिटल नवाचार के उपयोग पर भारत के विशेष बल को दशार्ती है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल भारतीय कार्बन बाजार के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए एक केंद्रीय डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा।

पोर्टल का उद्घाटन करते हुए श्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन में जलवायु प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि जलवायु संबंधी उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास साथ-साथ चल सकते हैं।

'48 घंटे के अंदर खोलो हर्मूज स्ट्रेट वरना तबाह कर दूंगा', ट्रंप ने दी ईरान को धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि उसने अगले 48 घंटे के भीतर हर्मूज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई

बिजली संयंत्रों को "निशाना बनाकर पूरी तरह तबाह कर देगा।" इसमें ईरान का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र भी शामिल होगा। ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने ईरान से जरूरी रास्ता खोलने की बात की है, जिसे ईरान पर वर-इजराइली हमले और उसके जवाबी हमलों की शुरूआत के बाद से ईरानी सेना ने रोक रखा है।

सम्पादकीय

खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागना आत्मघाती कदम!

ईंरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को हमला करके दो बातों को स्पष्ट कर दिया है— पहला यह कि सत्ता परिवर्तन तक वह ईंरान पर गोले बरसाता रहेगा और दूसरा यह कि वह न्यूक्लियर के मामले में ईंरान को किसी भी तरह की छूट देने वाला नहीं है।

दरअसल ईंरान ने जिस तरह खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागकर उन सभी को एकजुट किया है।

दरअसल अमेरिका और इजारयल चाहते हैं कि यह युद्ध लम्बा चले।

इसलिए ये दोनों ही चाहते हैं कि ईंरान के सैन्य प्रातिष्ठानों और न्यूक्लियर पैसिलिटी को तबाह करके ईंरान को घुटनों पर लाया जाए। ईंरान तो ध्यान भटकाने के लिए खाड़ी देशों को निशाना बना ही रहा है। लेकिन यह हथवंडा भी ईंरान का उलटा ही पड़ता दिख रहा है। ईंरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर को एक साथ निशाना बनाकर तीनों को अपना दुश्मन बना लिया और खाड़ी के देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी ईंरान के न्यूक्लियर पैसिलिटी को तबाह कर दे। ईंरान को इस बात की गलतफहमी थी कि चीन और रूस उसके साथ खड़े होंगे किन्तु इन दोनों ने ठेंगा दिखा दिया। असल में रूस के साथ ईंरान का एक समझौता हुआ है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि यदि ईंरान पर कोई हमला हुआ तो रूस उसकी रक्षा के लिए एस-400 देगा। लेकिन जब इजरायल और अमेरिका ने ईंरान पर हमला किया तो तेहरान में बैठे ईंरानी हुक्मरानों ने रूस से एस- 400 की मांग की। लेकिन रूस ने टका सा जवाब देते हुए पूछा कि अभी जो हमला हुआ है वह तो आतंकी ठिकानों पर हुआ है, ईंरान पर हमले हुए ही कहां है। हक्का-बक्का ईंरान बोले भले ही नहीं किन्तु उसे अब इस बात का एहसास हो गया कि उसकी मदद करके चीन और रूस खाड़ी के देशों को नाराज नहीं कर सकते। आज तो स्थिति यह कर दी है तेहरान ने कि खाड़ी देश खुलकर अमेरिकी और इजरायली हमलों का समर्थन कर रहे हैं। रूस और चीन दोनों ही खाड़ी देशों को नाराज करने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि ईंरान के लिए भला रूस और चीन अमेरिका एवं इजरायल से भी नाराजगी क्यों लें? रही बात भारत की तो भारत जहां इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, वहीं वह किसी भी पक्ष की तरफ खड़ा नहीं दिखना चाहता। भारत अपने भले-बुरे के बारे में अच्छी तरह जानता है। भारत यह भी जानता है कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। भारत को अपने राष्ट्रीय हित के मुताबिक ही अपनी वूटनीति अपनानी है, भारत कर भी वही रहा है। वूटनीति कब किन कारकों के अधीन हो जाती है। इसका एक ही मापदण्ड है राष्ट्रीय हित और रणनीतिक साझेदारी। भारत को बहुत ही सावधानी से इस बवाल से दूरी बनाए रखने की जरूरत है। ईंरान रणनीतिक सूझबूझ से न तो हमले कर रहा है और न ही यह संकेत दे रहा है कि अब तेहरान की नीति शांति और समझौता चाहती है। इसलिए खाड़ी के देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि वह सबसे पहले तो ईंरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करे और फिर मौजूदा शासन को अन्यथा इस क्षेत्र में अशांति और युद्ध का माहौल बना रहेगा। यही कारण है कि अमेरिका ने शनिवार को ही यह बयान भी दिया था कि वह न्यूक्लियर ईंरान से निकाल लेगा। बहरहाल जिस तरह ईंरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध में सक्रियतापूर्ण पहल कर रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि जहां अमेरिका व इजरायल रणनीति बनाकर ईंरान के सैन्य एवं न्यूक्लियर प्रातिष्ठानों को बर्बाद कर रहे हैं वहीं ईंरान बिना स्ट्रैटजिक प्लानिग के ही अपनी मिसाइल के जखीरे को खाली कर रहा है। उसे इस बात का अनुमान ही नहीं है कि वह जो कर रहा है, उसके परिणाम क्या होंगे। यह स्थिति कदाचित इसलिए है कि जिस रणनीतिक सैन्य कौशल और राजनीतिक सत्ता के समझ की जरूरत है, वह ईंरान में नहीं रही। बदहवासी से नहीं बल्कि युद्ध जीतने के लिए धैर्य एवं रणनीतिक समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है किन्तु दुर्भाग्य से ईंरान धैर्य का परिचय नहीं दे रहा है और इजरायल तथा अमेरिका चाहते हैं कि उनको लक्ष्य जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए।

आईआईटी बॉम्बे में 'भारत इनोवेट्स डीप-टेक प्री-समिट' का उद्घाटन किया गया

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने दो दिवसीय राष्ट्रीय डीप-टेक शोकेस का उद्घाटन किया; 3,000 से अधिक आवेदनों में से चयनित 137 स्टार्टअप्स मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे

भारत के सर्वश्रेष्ठ डीप-टेक स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार किया जा रहा है

(जीएनएस)।

भारत के सबसे आशाजनक डीप-टेक उद्यमों के राष्ट्रीय प्रदर्शन के रूप में आयोजित होने वाले 'भारत इनोवेट्स डीप-टेक प्री-समिट' का उद्घाटन आज मुंबई स्थित आईआईटी बॉम्बे परिसर के एस्पायर झ आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क फाउंडेशन में किया गया।

दो दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) के अध्यक्ष प्रो. अजय कुमार सूद ने भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

इस विशिष्ट कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. अभय करंदीकर, आईआईटी बॉम्बे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन तथा आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

यह प्री-समिट भारत इनोवेट्स 2026 यात्रा का प्रारंभिक चरण है, जिसका समापन जून 2026 में फ्रांस के नीस शहर में भारत के वैश्विक नवाचार प्रस्तुतीकरण के साथ होगा। यह कार्यक्रम भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का हिस्सा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।

अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि प्रो. अजय कुमार सूद ने भारत की तकनीकी नेतृत्व क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डीप-टेक नवाचार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीकों को आगे बढ़ाने में शैक्षणिक संस्थानों, शोध तंत्र और स्टार्टअप्स की भूमिका को रेखांकित किया।

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत इनोवेट्स 2026 एक 'पूरे सरकार का प्रयास' है। यह दुनिया के सामने भारत की अत्याधुनिक डीप-टेक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा मंत्रालय को एक साझा मंच पर लाता है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल वैश्विक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने का भी प्रयास है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा के अंक नहीं, बल्कि समाज में सार्थक योगदान देना है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। उन्होंने निवेशकों और कॉरपोरेट्स से महानगरों से परे होनहार स्टार्टअप्स की पहचान करने का आ'ान किया।

आईआईटी बॉम्बे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन ने नवाचारकताओं और स्टार्टअप संस्थापकों से राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ काम करने का आ'ान किया और कहा कि वे भारत के नवाचार इतिहास का नया अध्याय लिख सकते हैं। उन्होंने नवाचारकताओं को भारत का राजदूत बताया और देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. अभय करंदीकर ने भारत के नवाचार परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां लगभग 2 लाख स्टार्टअप और करीब 125 यूनिकॉर्न हैं कंपनिया। उन्होंने बताया कि 2017झ18 में यह संख्या केवल 24 यूनिकॉर्न थी। वर्तमान में भारत में 1,000 से अधिक निवेशक सक्रिय हैं और हाल के वर्षों में लगभग 70झ80 अरब रुपये का वेंचर कैपिटल भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया गया है।

उन्होंने डीप-टेक वित्तपोषण में कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि कुल वेंचर कैपिटल निवेश में से केवल 4झ5 अरब डॉलर ही डीप-टेक क्षेत्र में गया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष को मंजूरी दी, जो निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास और स्टार्टअप्स को इक्विटी भागीदारी और दीर्घकालिक वित्तपोषण के माध्यम से समर्थन देगा। इस फंड के प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और बीआईआरएसी (डीबीटी) को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही वैकल्पिक निवेश कोष और आईआईटी अनुसंधान पार्कों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। डीएसटी वर्तमान में साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और निधि सीड सपोर्ट योजनाओं के माध्यम से भारत के अनुमानित 8,000-10,000 डीप-टेक स्टार्टअप में से लगभग 30-40% का पोषण कर रहा है।

आईआईटी और आईआईएससी के पारिस्थितिकी तंत्र की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर करंदीकर ने कहा, "डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने में आईआईटी और आईआईएससी की बड़ी भूमिका है।"

आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे ने स्वागत भाषण में कहा कि भारत इनोवेट्स केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक डीप-टेक इकोसिस्टम है, जो तीन स्तंभों-शिक्षा प्रणाली, रणनीतिक निवेशक और कॉपोरेट सेक्टर पर आधारित है, जो तकनीक को वास्तविक प्रभाव में बदलने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि देशभर से 3,000 से अधिक स्टार्टअप आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कड़े बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद 13 थीमैटिक क्षेत्रों में 137 सर्वश्रेष्ठ डीप-टेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया।

उद्घाटन के बाद गणमान्य लोगों ने स्टार्टअप प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां उन्होंने स्टार्टअप संस्थापकों से बातचीत की और उनके नवाचारों का मुआयना किया। 70 से अधिक स्टार्टअप्स ने विभिन्न पिच सत्रों में अपने विचार रखे, जिसके बाद निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने रिवर्स पिच के माध्यम से निवेश के प्राथमिक क्षेत्रों और उद्योग की तकनीकी आवश्यकताओं पर चर्चा की। इसमें प्राथमिकता वाले निवेश क्षेत्रों और उद्योग-प्रेरित तकनीकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

भारत इनोवेट्स 2026 डीप-टेक प्री-समिट भारत के नवाचार इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाता है और उभरते स्टार्टअप्स को निवेशकों, उद्योग जगत और नीति-निमार्ताओं से जुड़ने का राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम में 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों-एडवांस्ड कंप्यूटिंग, हेल्थकेयर एवं मेडटेक, स्पेस एवं डिफेंस, एनर्जी एवं सस्टेनेबिलिटी, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज एवं मोबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी, नेक्स्ट-जेन कम्युनिकेशन, एग्री एवं फूड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्री 4.0 तथा आपदा प्रबंधन में नवाचार प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

भारत इनोवेट्स के बारे में:

भारत इनोवेट्स 2026, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय के रणनीतिक मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में विकसित अनुसंधान आधारित तकनीकी नवाचारों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है।

यह कार्यक्रम 22 मार्च 2026 को भी जारी रहेगा, जिसमें अतिरिक्त स्टार्टअप पिच सत्र, नीति चर्चा, निवेशक सहभागिता और ग्रैंड फिनाले एवं पुरस्कार समारोह आयोजित होगा, जहां सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप प्रस्तुतियों को सम्मानित किया जाएगा।

'एक स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को सुदृढ़ बनाना: पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने मॉक ड्रिल में पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया'

(जीएनएस)।

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने एक स्वास्थ्य पर चौथी वैज्ञानिक संचालन समिति की सिफारिशों के अनुरूप, 20 मार्च 2026 को एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में "मॉक ड्रिल के दौरान पहचानी गई कमियों को दूर करना" विषय पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया।

राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत तैयारियों को सुदृढ़ करने के प्रयासों के तहत, परिचालन तत्परता, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, प्रयोगशाला प्रतिक्रिया प्रणालियों, जैव सुरक्षा और जैव संरक्षण प्रथाओं और आपातकालीन संचार प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करने के लिए दो राष्ट्रीय स्तर के मॉक ड्रिल - "विषाणु युद्ध अभ्यास" (अगस्त 2024) और "वायरल संक्रमण अभ्यास" (नवंबर 2025) - आयोजित किए गए।

कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य इन मॉक ड्रिल से प्राप्त प्रमुख सबक के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को जागरुक करना और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए एक संरचित और समयबद्ध दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना था जिससे एक

रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया ढांचे को और मजबूत किया जा सके।

इस कार्यशाला में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन सत्र में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के सचिव श्री नरेश पाल गंगवार; डीएएचडी के पशुपालन आयुक्त डॉ. नवीन बी. महेश्वरप्पा; डीएएचडी के अपर सचिव (पशुधन स्वास्थ्य) श्री राम शंकर सिन्हा, डीएएचडी के संयुक्त सचिव डॉ. मुथुकुमारसामी बी.; और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) रंजन दास शामिल थे।

अपने संबोधन में प्रोफेसर सूद ने कहा कि मनुष्यों में उभरने वाली लगभग 60-70 प्रतिशत संक्रामक बीमारियाँ पशुओं से उत्पन्न होती हैं। उन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण विज्ञान और डेटा-आधारित नीति निर्माण को एकीकृत करने वाले एक समन्वित ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की सिफारिशों से उत्पन्न राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन, उभरते स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए समन्वित और अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि महामारी की तैयारी के लिए कई मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को शामिल करते हुए एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कार्यशाला की चर्चाएँ भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने सभी स्तरों पर जागरूकता, लक्षित क्षमता विकास और प्रभावी संचार रणनीतियों के महत्व पर जोर देते हुए, प्रकोप प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण मानवीय पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की जिनमें मॉक ड्रिल और तैयारी आकलन को संस्थागत बनाना; बीएसएल-3 पारिस्थितिकी तंत्र सहित एकीकृत निगरानी और प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूत करना; केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ाना; शासन ढांचे में सुधार करना; निरंतर क्षमता विकास में निवेश करना; और पूर्वानुमान तथा प्रतिक्रियात्मक प्रणालियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। प्रो. सूद ने डीएएचडी के प्रयासों की सराहना की और दोहराया कि मॉक ड्रिल समन्वय और परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण तनाव परीक्षण के रूप में कार्य करती हैं और कहा, "शांति के समय जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा।"

डीएएचडी के सचिव श्री नरेश पाल गंगवार ने महत्वपूर्ण तैयारियों की कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मॉक ड्रिल के महत्व पर जोर दिया। कोविड-19 और बार-बार होने वाले इन्फ्लूएंजा प्रकोपों से मिले सबक का हवाला देते हुए, उन्होंने निगरानी प्रणालियों, प्रयोगशाला नेटवर्क और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने में सिमुलेशन अभ्यासों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और भविष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाना है।

इस कार्यशाला में प्रमुख मंत्रालयों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, आईसीएमआर, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान, एनसीडीसी, आईसीएआर, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, डीएएचडी, एनएससीएस, एनडीएमए, बीएसएल 3 नेटवर्क, एक स्वास्थ्य के राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पशुपालन विभाग, आईडीएसपी के तहत राज्य निगरानी अधिकारी और साथ ही पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्र शामिल थे।

इस कार्यशाला में रोग प्रकोप प्रतिक्रिया पर एक टेबल टॉप अभ्यास - "संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास (एसपीए)" - और "एक्स किटाणु संक्रमण - वैश्विक सुरक्षा: स्वाध्याय से अभ्यास तक (केएस-वीएस-सैट)" शीर्षक से एक सिमुलेशन अभ्यास शामिल था। उसका समन्वय भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने किया।

कार्यशाला का समापन सभी प्रमुख हितधारकों की ओर से पहचानी गई कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने और एक स्वास्थ्य ढांचे के तहत भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया संरचना को और सुदृढ़ करने की मजबूत सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पर बैठक की अध्यक्षता की

भागीरथी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए हितधारकों का समन्वय आवश्यक है: श्री भूपेंद्र यादव

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (बीईएसजेड) पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की।

बैठक में विचार-विमर्श बीईएसजेड अधिसूचना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर केंद्रीत था। चचाओं में संतुलित एवं सतत विकास दृष्टिकोण के माध्यम से पारिस्थितिक प्राथमिकताओं को स्थानीय आकांक्षाओं एवं आजीविका के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

केंद्रीय मंत्री ने गंगा नदी के उद्गम स्थल भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील

क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक संरचित एवं समन्वित संरचना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित अध्ययनों, एकीकृत विकास योजना, स्पष्ट रूप से परिभाषित संस्थागत तंत्रों और सुदृढ़ निगरानी एवं प्रवर्तन प्रणालियों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अवैज्ञानिक विकास अक्सर ऐसी आपदाओं का कारण बनता है जिन्हें टाला जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने जोखिम कम करने के लिए सतर्क एवं सूचित दृष्टिकोण अपनाने का आ'ान किया।

श्री यादव ने हितधारकों के बीच समन्वय के महत्व पर भी प्रकाश डाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण संरक्षण उपायों को विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ सुचारू रूप से संरेखित किया जा सके, जिससे भागीरथी क्षेत्र में पारिस्थितिक अखंडता एवं सामुदायिक कल्याण दोनों की रक्षा हो सके।

इस बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, निगरानी समिति के सदस्य, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सरकार ने बजट 2025-26 के अनुरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निमार्ताओं और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन किया

संशोधनों से कवरेज बढ़ेगा, अनुपालन का बोझ कम होगा और निर्यातक एमएसएमई को लक्षित प्रोत्साहन मिलेगा

संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक के ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं

(जीएनएस)।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) जनवरी 2025 में शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए स्वीकृत ₹100 करोड़ तक की ऋण सुविधा के लिए 60% गारंटी कवरेज

प्रदान करती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ संशोधन किए गए हैं।

मौजूदा 'एमसीजीएस-एमएसएमई' योजना में संशोधनः

अग्रिम अंशदानः 5% अग्रिम अंशदान वापसी योग्य है, चौथे वर्ष से आगे प्रत्येक वर्ष 1% वापसी योग्य है, बशर्ते ऋण खाते का प्रदर्शन संतोषजनक हो।

पात्रताः सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी इस योजना में शामिल किए गए हैं।

मशीनरी/उपकरणों के लिए न्यूनतम परियोजना लागतः उपकरणों/मशीनरी की लागत परियोजना लागत के 60% तक कम कर दी गई है (पहले यह 75% थी)।

गारंटी की अवधिः गारंटी 10 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी।

निर्यातकों के लिए योजना में विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं:

पात्र निर्यातकः लाभ कमाने वाली इकाइयाँ जिन्होंने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में अपने बिक्री कारोबार का कम से कम 25% निर्यात किया हो और कुछ निर्यात प्राप्ति शर्तों को पूरा करती हों। गारंटीकृत ऋण राशिः 20 करोड़ रुपये। अग्रिम योगदानः ऋण राशि का 2% (अधिकतम 40 लाख रुपये); गारंटी अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष में 1 % की वापसी। गारंटी कवरेजः डिफॉल्ट राशि का 75%। गारंटी शुल्कः पहले वर्षः शून्य; उसके बाद, प्रत्येक वर्षः बकाया ऋण का 0.50%। संशोधित योजना का विवरण एनसीजीटीसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रमुख प्रभाव भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का योगदान लगभग 30% और निर्यात में 45% से अधिक है, साथ ही इससे 35 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है। "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ एमएसएमई की आवश्यकता है। एमसीजीएस-एमएसएमई योजना में किए गए संशोधनों से एमएसएमई, जिनमें निर्यातक एमएसएमई भी शामिल हैं, उनको संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि होने की उम्मीद है जिससे भारत के विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

तेलंगाना में 'छह गारंटी' पर घमासान, केटीआर ने कांग्रेस सरकार से पूछा- आखिर कहां गई वादों वाली फाइल?

(जीएनएस)। तेलंगाना की राजनीति में 'छह गारंटी' को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष K. T. Rama Rao ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Rahul GaQdhi ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से स्पष्ट वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में छह गारंटी को कानून का रूप दिया जाएगा।

KTR ने कांग्रेस को याद दिलाए ये अधूरे चुनावी वादे

KTR ने कहा कि यही छह गारंटी कांग्रेस की चुनावी जीत का आधार थीं। उनके अनुसार किसानों को साल में दो फसलों के लिए 15,000 रुपये की सहायता, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद और छात्रों को 5 लाख रुपये तक का 'विद्या भरोसा कार्ड' देने का वादा किया गया था।

ढाई साल बाद भी नहीं बन पाया कानून

केटीआर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से फाइल पर हस्ताक्षर करने की बात कही थी और राज्यपाल के अभिभाषण में भी बिल विधानसभा में लाने की घोषणा की गई थी। लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी यह कानून नहीं बन पाया है।

आखिर कहां गई वादों वाली फाइल?

KTR ने तंज कसते हुए कहा कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर वह फाइल कहां गई। उन्होंने कहा कि सरकार को आसान बनाने के लिए इफ्र अब वही प्रावधान शामिल करते हुए एक प्राइवेट मेंबर बिल अगले सप्ताह विधानसभा में पेश करेगी, ताकि छह गारंटी को वैधानिक दर्जा दिया जा सके।

क्या हैं कांग्रेस को होगा नुकसान?

विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी राजनीतिक समीकरणों और जनता के बीच वादों की विश्वसनीयता को लेकर यह मुद्दा तेलंगाना की राजनीति में बड़ा चुनावी विषय बन सकता है। कांग्रेस सरकार की ओर से इस बयान पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

जगद्गुरु स्वामी चक्रपाणि नन्द गिरि जी महाराज का प्रयागराज में भव्य स्वागत हुआ

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ/प्रयागराज

श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के जगद्गुरु पद पर अभिषिक्त होने के उपरांत परम पूज्य जगद्गुरु स्वामी चक्रपाणि नन्द गिरि जी महाराज का प्रथम आगमन तीर्थराज प्रयागराज में हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेशानुसार सर्वप्रथम प्रातःकाल त्रिवेणी संगम पहुंचकर विधिवत पूजन-अर्चन किया।

तत्पश्चात वेणी माधव मंदिर में दर्शन-पूजन किया, उसके उपरांत महर्षि भारद्वाज आश्रम में सप्तऋषियों का स्मरण एवं दर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने संपूर्ण प्रयागराज धाम के प्रमुख तीर्थों के दर्शन किए तथा माँ ललिता देवी मंदिर में श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना किया।

इसके उपरांत जगद्गुरु महाराज मौज गिरी, जूना अखाड़ा, कीडगंज पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षक पूज्य श्री हरि गिरि जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा धर्म एवं राष्ट्रहित विषयों पर विस्तृत चिंतन किया।

इस पावन अवसर पर प्रयागराज के वरिष्ठ भाजपा नेता कुमार नारायण अपने दर्जनों साथियो के साथ जगद्गुरु स्वामी चक्रपाणि जी महाराज का पुष्पमाला एवं पटका पहनाकर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि स्वामी चक्रपाणि जी महाराज को जूना अखाड़ा द्वारा जगद्गुरु की उपाधि प्रदान की गई है। उन्होंने घोषणा की कि प्रयागराज सहित पूरे देश में जगद्गुरु महाराज के सम्मान में भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का भी पूरे देश में अभिनंदन एवं स्वागत किया जाएगा, शीघ्र ही प्रयागराज में स्वामी जी के लिए एक विशाल स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम में केपी ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के सुपुत्र कौशलेंद्र नाथ सिंह "सौरभ" सहित अनेक श्रद्धालुओं ने जगद्गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। कौशलेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि स्वामी चक्रपाणि जी महाराज को जगद्गुरु पद पर आसीन किया गया है।

इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए जगद्गुरु स्वामी चक्रपाणि जी महाराज ने कहा कि शीघ्र ही पूरे देश में 'हिंदू स्वाभिमान यात्रा' निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य धर्म रक्षा, गौ रक्षा, मंदिरों की सुरक्षा एवं संतों तथा गौभक्तों की रक्षा सुनिश्चित करना होगा।

पत्रकारों द्वारा वृंदावन में गौभक्त परसा बाबा की हत्या के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोषियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे और शीघ्र ही न्याय सुनिश्चित होगा।

जगद्गुरु महाराज ने कहा कि अपने पूज्य गुरुदेव से विमर्श उपरांत श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, विभिन्न हिंदू संगठनों एवं धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रव्यापी 'हिंदू स्वाभिमान यात्रा' प्रारंभ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य सदैव धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा एवं हिंदू स्वाभिमान की रक्षा रहा है। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख पक्षकार के रूप में उनकी भूमिका, राष्ट्रविरोधी शक्तियों के विरुद्ध उनके साहसिक कदम तथा हिंदू समाज के सम्मान हेतु उनके द्वारा किए गए कार्य सर्वविदित हैं। यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्रवादी एवं धर्मनिष्ठ समाज का सम्मान है।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे सुमित श्रीवास्तव, आर.के. श्रीवास्तव, दिलीप श्रीवास्तव (दीपू), भानु प्रताप सिंह, संचित निधि, अमित श्रीवास्तव (रिंकू), धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव (समीर), कौशलेंद्र बहादुर, राकेश श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे '

करेली पुलिस ने लिलहर मेले से गुम 5 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा

(जीएनएस)।

पीलीभीत। थाना करेली पर नियुक्त महिला सुरक्षा केंद्र टीम ने ग्राम लिलहर के चैत्र अमावस्या मेले में गुम हुई 5 वर्षीय बालिका शगुन को तलाशकर उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले इस कार्य की ग्रामीणों ने खूब सराहना की।दिनांक 18 मार्च 2026 को बनवसा (उधम सिंह नगर, उत्तराखंड) निवासी श्रीमती राखी अपनी पुत्री शगुन को लिलहर मेले में लेकर आई थीं। अचानक शगुन के खो जाने की सूचना मिलते ही मेले में तैनात महिला सुरक्षा केंद्र टीम व करेली पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू कर दी। टीम के सतर्क प्रयासों से कुछ ही देर में बालिका सकुशल बरामद हो गई, जिसे मां श्रीमती राखी को सौंप दिया गया।पुलिस टीम में शामिल रहे:थानाध्यक्ष श्री विपिन शुक्लाउ0नि0 श्री श्रीकृष्ण (प्रभारी एम०एस० के०)म0का0 मुनीका० आशुतोष राणाका० यशवीर सिंहका० सन्नीआमजनमानस ने पुलिस टीम के त्वरित कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया।

पीलीभीत में ईद-उल-फित्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज सकुशल संपन्न, एसपी ने लिया जायजा

(जीएनएस)।

पीलीभीत। जिले में ईद-उल-फित्र के पवित्र अवसर पर जिलाधिकारी पीलीभीत एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चंद्रोदय के बाद ईद की नमाज विभिन्न प्रमुख मस्जिदों एवं ईदगाहों में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हो गई। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की तत्परता से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने का मौका नहीं मिला।

ईद-उल-फित्र का त्योहार शनिवार को चांद दिखने के बाद दोपहर करीब 12 बजे से शुरू हो गया। जिले भर में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने विभिन्न स्थानों पर एकत्र होकर नमाज अदा की। प्रमुख स्थलों में गणेश मंदिर के पास ईदगाह, कोतवाली क्षेत्र की जामा मस्जिद, सदर कोतवाली के आसपास के इलाके तथा गजलाक्ष्मी मंदिर रोड पर स्थित ईदगाह शामिल रहे। इन सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पीआरवी (पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल) वाहनों के माध्यम से लगातार गश्त की जा रही थी तथा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई।

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने भ्रमण के दौरान थानों के प्रभारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान शांति एवं भाईचारे को कायम रखने के लिए सभी सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की शरारती तत्वों की सख्ती से निगरानी की जाए तथा भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने भी स्थानीय लोगों से अपील की कि वे आपसी सद्भाव बनाए रखें तथा त्योहार की खुशी में सभी मिल-जुलकर भाग लें।

इस अवसर पर एसपी ने सभी से शांति व भाईचारे की अपील की। उन्होंने कहा कि पीलीभीत जिला सदैव शांति का प्रतीक रहा है तथा सभी धर्मों के लोग यहां परिवार की तरह रहते हैं। ईद के पावन पर्व पर सभी को बधाई देते हुए उन्होंने आने वाले समय में भी इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखने का आ'ान किया। जिले भर में त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने से प्रशासनिक अधिकारी संतुष्ट दिखे।

लोकल लोगों ने प्रशासन की व्यवस्था की सराहना की तथा कहा कि ऐसी सक्रियता से त्योहार सुरक्षित रहते हैं। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुनगढ़ी पुलिस ने बिजली तार चोरी का किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)।

पीलीभीत।

थाना सुनगढ़ी पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए बिजली के तार के तीन बंडल (कुल वजन 55.600 किलोग्राम) बरामद किए हैं।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत की गई। दिनांक 21 मार्च 2026 को थाना सुनगढ़ी पुलिस टीम ने मुकदमा संख्या 112/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों में हरिओम (34 वर्ष), सतीश (35 वर्ष) निवासी ग्राम रोहड़ी, थाना दातागंज, जनपद बदायूं तथा विमल (28 वर्ष) निवासी खजुरिया ब्रह्मनान, थाना बिथरी चैनपुर, जनपद बरेली शामिल हैं। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी विमल के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें विभिन्न धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है।

इस सफल कार्रवाई में उपनिरीक्षक आकाश तेवतिया, उपनिरीक्षक विष्णु सिंह सोलंकी सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सांसद जितिन प्रसाद का ट्रांस शारदा दौरा, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान व विकास योजनाओं का आश्वासन

(जीएनएस)।

पीलीभीत। जनपद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के ट्रांस शारदा इलाके में विभिन्न गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया।

दौरे की शुरूआत इंडो-नेपाल सीमा से सटे ग्राम पंचायत बैल्हा से हुई, जहां ग्रामीणों ने शारदा नदी के कटान से बचाव के लिए तटबंध निर्माण, किसानों को भूमि अधिकार दिलाने, सड़क, अस्पताल और कॉलेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी। मंत्री ने संबंधित समस्याओं की जांच कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

इसके बाद वह सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज पहुंचे, जहां किसान नेता देव स्वरूप पटेल समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगे भरतपुर नेहरू नगर स्थित एलबीएस इंटर कॉलेज चौराहे पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने कॉलेज प्रबंध समिति के गठन, अस्पताल में नियमित चिकित्सकों की तैनाती और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को पूरा कराने की मांग उठाई। साथ ही, वन विभाग की भूमि पर वर्षों से रह रहे कटान पीड़ितों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने शारदा नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण का उल्लेख करते हुए सरकार की विकास योजनाओं को गिनाया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद के माध्यम से प्राप्त समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी।

कार्यक्रम के अंत में उन्होंने आगामी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। इस दौरान विधायक बाबूराम पासवान, क्रांतिकारी पार्टी अध्यक्ष देव स्वरूप पटेल रितुराज पासवान, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिलाएं और ग्रामीण मौजूद रहे।

जनपद बदायूं में जनपद बदायूं के सभी कस्बों में बड़े ही हर्षोल्लास साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व

जनपद बदायूं में ईद के पावन पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं एवं जिला अधिकारी के साथ विभिन्न ईदगाहों, मस्जिदों एवं प्रमुख मार्गों/आवागमन के रास्तों का सघन एवं व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से आकलन करते हुए ड्यूटी पर तैनात समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च स्तरीय सतर्कता एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए।

विशेष रूप से संवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने, प्रभावी भीड़ नियंत्रण, सुचारु यातायात प्रबंधन तथा कानून-व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु स्पष्ट एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संचालित की जाएं।

प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ईद का पर्व आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता एवं शांति के वातावरण में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो।

पीलीभीत में ईद-उल-फितर सौहार्द के साथ संपन्नः उ्ट-रढ ने खुद संभाला मोर्चा, शांति और भाईचारे के बीच लोगों ने मनाया त्यौहार

(जीएनएस)।

पीलीभीत में ईद-उल-फितर का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिले की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने स्वयं मोर्चा संभाला और नगर क्षेत्र का सघन भ्रमण किया।

त्योहार के मद्देनजर शनिवार सुबह से ही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच अकीदतमंदों ने शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने, भीड़ नियंत्रण करने और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए।

नमाज के बाद लोगों से मुलाकात

नमाज संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम धर्मगुरुओं, प्रबुद्धजनों और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और त्योहार को आपसी प्रेम, शांति तथा भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। अधिकारियों ने बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

ड्रोन और उउळश से रखी गई निगरानी

पुलिस अधीक्षक ने सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को लगातार गश्त के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ पुलिस टीमें तैनात रहीं। प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई।

प्रशासन की मुस्तैदी से सब कुछ शांत

पीलीभीत पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रशासन की सक्रियता और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से ईद का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करने की टेली-लॉ पहल (दिशा) के तहत आयोजित किया जा रहा है 2026 का क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला

कार्यशाला को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे और न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने तथा शासन में डिजिटल समाधान की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यशाला टेली-लॉ और न्याय तक पहुंच से संबंधित अन्य पहलों की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने पर केंद्रित विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है

(जीएनएस)।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में 22 मार्च 2026 को शाम 4:00 बजे से क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करने (दिशा) की टेली-लॉ पहल के तहत आयोजित 2026 का क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। यह कार्यशाला 22 मार्च 2026 को शाम 4:00 बजे से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में आयोजित की जाएगी।

यह कार्यशाला विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी-सक्षम कानूनी सेवाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच को मजबूत करने और प्रमुख हितधारकों के बीच जानकारीपूर्ण विचार-विमर्श को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है।

कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों के आगमन और स्वागत के साथ होगा, जिसके बाद दिशा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जो पहुंच और अंतिम छोर तक संपर्क का प्रतीक है। गणमान्य व्यक्ति मंच पर अपने-अपने स्थान ग्रहण करेंगे, जिसके बाद दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव होगा, जिसे स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को याद किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में न्याय विभाग के सचिव स्वागत भाषण देंगे, जिसमें कार्यशाला का संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में दिशा योजना की प्रगति को प्रदर्शित करने वाला एक सत्र होगा, जिसमें टेली-लॉ पैनल के वकीलों, ग्राम स्तरीय उद्यमियों और लाभार्थियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद शामिल होंगे, जो जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी-आधारित कानूनी सेवाओं के प्रभाव को दशाएंगे।

इस कार्यक्रम में हरियाणा के विधि महाविद्यालयों द्वारा शुरू की गई निःशुल्क कानूनी सेवाओं (प्रो बोनो) की पहलों पर एक खंड भी शामिल होगा, जिसमें संकाय सदस्यों और सामुदायिक कानूनी सेवा में लगे छात्रों द्वारा अनुभव साझा किए जाएंगे।

इस आयोजन के अंतर्गत, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों पर पांच ई-पुस्तकों का औपचारिक विमोचन किया जाएगा, जो स्वदेशी कानूनी ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में योगदान देंगी। इसके अतिरिक्त, दिशा योजना पर दूरदर्शन द्वारा एक वृत्तचित्र का भी विमोचन किया जाएगा, जिसमें इसके दृष्टिकोण, कार्यान्वयन और देश भर में इसके प्रभाव को दशार्या जाएगा।

इस कार्यशाला को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे, जो न्याय तक पहुंच को मजबूत करने और शासन में डिजिटल समाधान की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे।

निमार्णाधीन धनाराघाट पुल का केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता पर सख्त निर्देश!

(जीएनएस)।

पीलीभीत। जिले में निमार्णाधीन धनाराघाट पुल का शनिवार को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी हासिल की।निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो। उन्होंने कहा, "पुल का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में समाप्त किया जाए, ताकि आम जनता को जल्द लाभ मिले। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।"कार्यदायी संस्था को सख्त हिदायत दी गई कि गुणवत्ता में कोई कमी न हो। मौके पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, अभियंता और संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने नैनी में प्रदेश सचिव के घर पर ईद मिलन मे समलित हुये

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ/प्रयागराज

हम भाईचारा चाहते हैं। एकता का संदेश देना चाहते हैं। वर्तमान सरकार भाईचारा नहीं नफरत चाहती है। ऐसी नफरत वादी सरकार को हम हटाने का काम करेंगे महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सब से निजात पाने का सिर्फ एक रास्ता है, सामाजिक न्याय। देश और प्रदेश की जनता पीडीए के माध्यम से लामबद्ध हो रही है। यह बातें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने नैनी में प्रदेश सचिव के घर पर ईद मिलन के दौरान कहीं।

नैनी में शनिवार को प्रदेश सचिव मोहम्मद शारिक के आवास पर ईद मिलन का आयोजन का किया गया। इस मौके पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। जहां उनका सभी ने जोरदार स्वागत किया।

प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में संविधान की सरकार बनाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव करना ही नहीं चाहती। सरकार को अब तक पंचायत चुनाव करा देना चाहिए। सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाहती है।

जातीय जनगणना पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने प्रश्न उठाया था। ऊंच, नीच की जाति में एक मिडिल क्लास की जाति भी है, जो शिक्षा और समाज से काफी दूर है। अंग्रेज जनगणना करा कर सभी का हिस्सा देना चाहते हैं, वर्तमान सरकार ने संविधान के समय ही तय किया था कि सरकार बनती है तो, देश की पिछड़ी जाति की भी जनगणना होगी, लेकिन नहीहुआ।

उन्होंने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार को हटाकर पड़ा कि सरकार बनाना है। जिससे संविधान सुरक्षित रहे। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने नवरात्र और ईद के एक साथ पड़ने पर कहा कि यह प्रकृति का स्वरूप है, जो आपसी भाईचारे का पर्व ईद और नवरात्रि एक साथ देखने को मिल रहा है। हम सभी को इसे मिलजुल कर मानना चाहिए।

भाइयों पे जानलेवा हमला मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ/प्रयागराज

प्रयागराज। यमुनानगर जोन के करछना तहसील स्थित ग्राम पंचायत पिपरांव के भटौली गांव में दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में श्याम बाबू भारतीया (22) पुत्र स्वर्गीय रामधनी भारतीया के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि उनके बड़े भाई रामबाबू भारतीया (32) के हाथ में चोट लगी है।

पुलिस के अनुसार गांव के ही अनिल कुमार भारतीया तथा उसके भाई श्याम बिहारी भारतीया, पुत्र जगदीश, पेशे से सफाईकर्मी हैं। इन

दोनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।

किसी तरह अपनी जान बचाकर दोनों भाई घर पहुंचे, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित पक्ष ने करछना थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

थाना प्रभारी करछना प्रवीण कुमार गौतम ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पीडीयूएनएएसएस ने डीओपीटी द्वारा प्रायोजित अनुभवात्मक शिक्षण उपकरणों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) ने नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में 16 से 20 मार्च, 2026 तक अनुभवात्मक शिक्षण उपकरण (ईएलटी) पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के तहत आयोजित किया गया था। यह सिविल सेवाओं में क्षमता विकास और प्रशिक्षण तंत्र को मजबूत करने पर सरकार के निरंतर प्रयास को दशार्ता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षकों में अनुभवात्मक अधिगम पद्धतियों का उपयोग करते हुए प्रभावी, शिक्षार्थी-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और प्रदान करने के लिए आवश्यक दक्षताओं का विकास करना था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सहभागिता बढ़ाने, व्यावहारिक अनुप्रयोग और वास्तविक दुनिया के संदर्भों के माध्यम से अधिगम परिणामों में सुधार करना था।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा सत्र संचालित किए गए जिनमें बीएसएफ के कमांडेंट श्री संदीप गुप्ता और व्याख्याता श्री लक्ष्मण मानिकपुरी शामिल थे। कार्यक्रम में केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, फील्ड आधारित शिक्षण और समूह अभ्यास जैसे कई अनुभवात्मक उपकरणों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में संवादात्मक और सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया।

इस प्रशिक्षण में व्यावहारिक अभ्यास, चिंतनशील अधिगम और सहयोगात्मक सहभागिता पर जोर दिया गया ताकि प्रतिभागी समकालीन शासन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावशाली प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर सके।

समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, पीडीयूएनएएसएस के निदेशक कुमार रोहित ने आधुनिक क्षमता विकास में अनुभवात्मक शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा:

'अनुभवात्मक शिक्षण उपकरण प्रशिक्षकों को गहन और परिणामोन्मुखी शिक्षण वातावरण बनाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ज्ञान को सेवा वितरण में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। पीडीयूएनएएसएस 'विकसित भारत' की परिकल्पना के अनुरूप एक सक्षम, उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण हेतु नवीन शिक्षण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।'

उन्होंने संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में डीओपीटी के प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।

इस कार्यक्रम में बीएसएफ, सीआईएसएफ, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान और ईपीएफओ सहित विभिन्न संगठनों के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के व्यावहारिक दृष्टिकोण और प्रासंगिकता की सराहना की।

इस अवसर पर पीडीयूएनएएसएस के मुख्य शिक्षण अधिकारी श्री रिजवानुद्दीन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समन्वय पीडीयूएनएएसएस के प्रथम वरिष्ठ अधिकारी श्री विजय कुमार ने किया। उन्होंने पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में कार्य किया।

पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर प्रमुख क्षेत्रों के बारे में नवीनतम जानकारी

(जीएनएस)।

पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों की नवीनतम जानकारी नीचे दी गई है। इनमें ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए समर्थन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

ईंधन की आपूर्ति और उपलब्धता

होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

कच्चा तेल/तेल शोधन कारखाने

सभी तेल शोधन कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है।

शोधन कारखानों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में वृद्धि की गई है।

खुदरा दुकानें

तेल विपणन कंपनियों द्वारा किसी भी परिचालन केंद्र (आरओ) में ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार जनता को एक बार फिर सलाह देती है कि वे घबराकर खरीदारी न करें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।

प्राकृतिक गैस

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिसमें डी-पीएनजी और सीएनजी परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति शामिल है। ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत के बराबर है।

भारत सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने सभी गैस क्षेत्रों में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।

आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल जैसी सीजीडी कंपनियों ने घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है।

पीएनजीआरबी ने सीडीजी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे आवेदन जमा करने और उपभोक्ता परिवारों को गैस आपूर्ति शुरू करने के बीच की समयावधि को कम करें।

भारत सरकार ने दिनांक 16.03.2026 के पत्र के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दिनांक 19.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी संबंधित केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि-

ट सीजीडी अवसंरचना से संबंधित सभी लंबित और नई अनुमतियों के तत्काल त्वरित निपटान और निपटारे के लिए संबंधित विभाग/निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किया जाए।

ट भविष्य में सीजीडी से संबंधित अनुमति अनुरोधों को संसाधित करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध व्यवस्था भी स्थापित किया जा सकती है।

ट सभी केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों/कॉलोनियों/अधिकारियों/कैंटीनों को भी यह सलाह दी गई है कि वे जहां भी उपलब्ध हो, पीएनजी का उपयोग करना शुरू कर दें।

भ भारत सरकार ने दिनांक 20.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में पीएनजी कनेक्शनों की संभावित मांग का व्यापक आकलन करें और इस अभ्यास के समन्वय के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करें।

भ भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के जवाब में, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने अपने सभी कार्यालयों को सीजीडी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर अर्थात प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निपटान करने की सलाह दी है।

ड्ट प्रमुख शहरों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं से एलपीजी के स्थान पर पीएनजी (पेट्रोलियम-जनित गैस) का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत मुख्यमंत्री का आभार

(जीएनएस)।

लखनऊ। आपको बहुत-बहुत बधाई एवं प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने उ०प्र० उद्योग व्यापार संगठन की वर्षों पुरानी मांग को मानते हुए निर्णय लिया है, कि आगे 01अप्रैल 2026 से प्रदेश के खाद्य, फूड, किराना, रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई आदि सभी खुदरा व थोक व्यापारियों को राहत देते हुए घोषणा की है कि अब फूड विभाग में मात्र ₹100 के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की सीमा 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है तथा 1 अप्रैल 2026 से पंजीकृत सभी लाइसेंस आजीवन कर दिए गए हैं यानी अब डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारी को मात्र ₹100 का पंजीकरण कराना होगा जो आजीवन के लिए मान्य होगा उसका रिनुवल कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश सरकार के द्वारा व्यापार संगठन की इस मांग को माने जाने के बाद प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों को लाभ होगा साथियों यह सब आप की मेहनत व संगठन की व्यापारियों के प्रति राहत दिलाने की सोच से संभव हो पाया है इसलिए आप सभी बधाई के पात्र है। हम प्रदेश के व्यापारी अपने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से प्रदेश सरकार के इस निर्णय का का हृदय से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं साथियों आप भी यह जानकारी अपने-अपने जिले व नगर के सभी व्यापारियों को मीडिया के माध्यम से दें और अखबारों में विज्ञप्ति दे ताकि जिले व नगर के व्यापारियों को उ०प्र० उद्योग व्यापार संगठन की इस उपलब्धि की जानकारी हो तथा व्यापारी इसका लाभ उठा सकें।

पीलीभीत में मिशन शक्ति 5.0 की धूमः एसपी सुकीर्ति माधव ने हरी झंडी दिखाकर निकाली भव्य बाइक रैली, महिलाओं का सम्मान-देश का अभिमान!

(जीएनएस)।

पीलीभीत, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए चल रहे मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत जनपद पीलीभीत में शुक्रवार को महिला जागरूकता हेतु एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया।रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक श्री सुकीर्ति माधव ने पुलिस लाइन पीलीभीत से हरी झंडी दिखाकर किया। यह रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर नकटादाना चौराहा, गौहनिया चौराहा, छतरी चौराहा होते हुए असम चौराहे तक पहुंची। रैली में "महिलाओं का सम्मान-देश का अभिमान" जैसे नारों के जरिए समाज के हर वर्ग तक महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम दहिया, सहायक पुलिस अधीक्षक सुश्री नताशा गोयल, क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात, जनपद की सभी शाखाओं की महिला उपनिरीक्षक, महिला मुख्य आरक्षी, महिला आरक्षी एवं पीआरवी कर्मियों ने प्रमुख रूप से भाग लिया।

यम दूत बनकर रोड पर दौड़ रही बाइक कार में मारी टक्कर।

(जीएनएस)।

हरदोई/कछौना थाना कासिमपुर गौसगंज में आम तौर पर एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती हैं वही आज तेज रफ़्तार बाइक सवार ने इनोवा कार में टक्कर मार दी। फिलहाल किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं हल्की फुल्की लगने की सूचना हैं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि थोड़ी बहुत बहस हुई फि लहाल मौके पर ही उपस्थित लोगों ने मामले को समझा बुझा का शांत कराया ज्यादा नुकसान न होने के कारण बाइक से इनोवा कार में टक्कर साइड में लगना ही रहा मामले को आगे न बढ़ा कर दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग से सुलह समझौता कर एक दूसरे के नुकसान की भरपाई कर दी गयी है। वहां उपस्थित स्थानीय लोगों ने कई घटनाओं को लेकर बाइक सवार को रूबरू करवाया और बाइक तेज न चलाने की सलाह दी। यातायात व्यस्त रहने वाला मार्ग होने के कारण यहां अक्सर कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती रहतीं हैं जिसके चलते लोगों को तेज रफ़्तार वाहन न चलाने की सलाह रहती हैं। जिस समय यह घटना घटी फि लहाल उस टाइम दुकानें बंद हो चुकी थी और लोग अपने घर जा चुके होते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा कम होने के कारण कोई बड़ी घटना का रूप नहीं बनी।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) अकादमी ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण तथा मान्यता बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा उत्कृष्टता का नेतृत्व करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

कार्यनीतिक साझेदारी से एक औपचारिक ढांचा तैयार होगा जहां एसएसबी अकादमी में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरआरयू अकादमिक मान्यता प्रदान करेगा

इस सहयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा में अकादमिक अनुसंधान और सीमा सुरक्षा बलों की व्यावहारिक तथा जमीनी आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में स्थापित आरआरयू का प्राथमिक उद्देश्य एसएसबी से संचालित मौजूदा और भावी पाठ्यक्रमों को मान्यता देना है

आरआरयू पेशेवर विकास के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एसएसबी कर्मियों को अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और क्षेत्र-आधारित कार्यशालाओं के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा

इस पहल से सीमा निगरानी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एसएसबी के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नवीनतम होने की उम्मीद है

इस पहल का उद्देश्य दोनों संस्थानों की प्रतिभाओं का लाभ उठाकर एसएसबी के भीतर निरंतर पेशेवर विकास के लिए एक मजबूत परितंत्र तैयार करना है

(जीएनएस)। देश के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में उठाए गए कदम में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) अकादमी ने अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ विशेष सुरक्षा पाठ्यक्रमों को संबद्ध और मान्यता देने के लिए आज आधिकारिक तौर पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। औपचारिक हस्ताक्षर समारोह दिल्ली में एसएसबी मुख्यालय में हुआ, जिसमें आरआरयू के प्रो-वाइस चांसलर प्रोफेसर (डॉ.) कल्पेश एच. वांड्रा; आरआरयू में संबद्धता और प्रत्यायन के डीन श्री अविनाश खरेल; और एसएसबी के महानिदेशक (डीजी) श्री संजय सिंघल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

यह कार्यनीतिक साझेदारी एक औपचारिक ढांचा तैयार करती है जहां राष्ट्रीय महत्व का संस्थान आरआरयू, एसएसबी अकादमी में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक मान्यता प्रदान करेगा। समझौते की शर्तों के तहत, दोनों संस्थानों ने संकाय विशेषज्ञता, शैक्षणिक उपकरण और विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं सहित संसाधनों के व्यापक आदान-प्रदान के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इस सहयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा में अकादमिक अनुसंधान और सीमा सुरक्षा बलों की व्यावहारिक तथा जमीनी आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है।

कार्यक्रम के दौरान, प्रोफेसर (डॉ.) कल्पेश एच. वांड्रा ने कहा कि यह सहयोग पहले से ही परिणाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि आरआरयू ने हाल ही में एसएसबी अधिकारियों के लिए एक विशेष "स्मार्ट सीमा प्रबंधन" पाठ्यक्रम आयोजित किया है। पेशेवर विकास के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, आरआरयू एसएसबी कर्मियों को अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और क्षेत्र-आधारित कार्यशालाओं के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस पहल से एसएसबी के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नवीनतम होने की उम्मीद है, जिसमें सीमा निगरानी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

एसएसबी महानिदेशक श्री संजय सिंघल ने बल के लिए आवश्यक शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए आरआरयू की क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस साझेदारी में अधिकारियों को सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा के उभरते परिदृश्य के अनुकूल तैयार करने के लिए उनका "कौशल विकास और पुनः कौशल" पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दोनों संस्थानों की प्रतिभाओं का लाभ उठाकर सशस्त्र सीमा बल के भीतर निरंतर पेशेवर विकास के लिए एक मजबूत परितंत्र बनाना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में स्थापित इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिसिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करना है। इसके लिए यह विशेषज्ञों के एक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक अनुशासित ढांचे के भीतर विशेष पेशेवर शिक्षा प्रदान करता है।

इस टङ्कव के तहत, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (फ्फ्च) ररइ द्वारा संचालित मौजूदा और भविष्य के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप, फ्फ्च के 'पाठ्यक्रमों के संयुक्त प्रत्यायन और प्रमाणन दिशानिदेर्शों' के आधार पर संबंधित उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र (उी१ॠं३ी), डिप्लोमा, ढक्ष् डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, स्नातक (ड्री'ङ्क१'२) या स्नातकोत्तर (टं२३ी१'२) की डिग्री प्रदान की जा सकती है।

इस साझेदारी में कार्यान्वयन के लिए एक तार्किक ढांचा शामिल है:

पाठ्यक्रम मूल्यांकनः आरआरयू प्रशिक्षण के घंटों और अकादमिक क्रेडिट की सामग्री की समानता निर्धारित करने के लिए एसएसबी प्रतिष्ठानों में वर्तमान पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेगा।

पाठ्यचर्या में वृद्धिः दोनों संस्थान विशिष्ट डिग्री या डिप्लोमा के लिए "अतिरिक्त क्रेडिट" आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम सामग्री या पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में सहयोग करेंगे।

मानकीकृत मूल्यांकनः आरआरयू कानून द्वारा आवश्यक उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के लिए एक मजबूत मूल्यांकन प्रक्रिया और ग्रेडिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा।

शैक्षणिक संपूर्णता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए, यह साझेदारी मौजूदा और अतिरिक्त पाठ्यक्रम सामग्री दोनों की आवधिक जांच और सत्यापन को अनिवार्य करती है। इस साझेदारी से यह सुनिश्चित होता है कि पाठ्यक्रम गतिशील बना रहे और उभरते सुरक्षा खतरों के प्रति उत्तरदायी रहे।

इसके अलावा, इसके तहत सशस्त्र सीमा बल अकादमी में एक समर्पित आरआरयू डेस्क की स्थापना की जाएगी। यह प्रशासनिक केंद्र डेटा का प्रबंधन करेगा, दिन-प्रतिदिन के संचार को सुव्यवस्थित करेगा, और मान्यता प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेगा, जिससे विश्वविद्यालय और अर्धसैनिक बल के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित होगा।

यह सहयोग गृह मंत्रालय के "एकीकृत प्रशिक्षण" दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सैद्धांतिक अनुसंधान और व्यावहारिक